

पहले मुख्य समाचार।

- पीएम किसान सम्मान निधि की बाइसवीं किस्त जारी। प्रदेश के दो करोड़ पन्द्रह लाख से अधिक किसान हुए लाभान्वित।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा- देश के विकास में ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहा यूपी।
- लोकसभा ने वर्ष दो हजार पच्चीस-छब्बीस के लिये पूरक अनुदानों को दी मंजूरी। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिये तीस हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन।
- प्रदेश में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आज और कल होगी लिखित परीक्षा। परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम से पीएम किसान सम्मान निधि की बाइसवीं किस्त जारी की। इससे देशभर के लगभग नौ करोड़ बत्तीस लाख किसानों के बैंक खातों में अट्ठारह हजार छः सौ चालीस करोड़ रुपये की धनराशि भेजी गई। प्रदेश के दो करोड़ पन्द्रह लाख से अधिक किसान भी इससे लाभान्वित हुए हैं। उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से चार हजार तीन सौ पैंतीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये भेजे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना छोटे किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है।

सम्मान निधि की योजना देश के छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक माध्यम बन गई। साथियों बीजेपी-एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा और साथियों बीते 11 वर्षों में देश के किसान के इर्द-गिर्द बीजेपी-एनडीए सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा कवच बना है। एमएसपी हो, सस्ता ऋण हो, फसल बीमा हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, यह योजनाएं किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। वाराणसी के किसान अंजनी कुमार ने किसान सम्मान निधि की किस्त मिलने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह धनराशि किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही है।

किसान सम्मान निधि बहुपयोगी साबित हुआ। छोटे किसानों के लिए तो यह प्राण जैसा काम कर रहा है। छोटे किसान पहले टाइम से खेती नहीं कर पाते थे, गुवाई नहीं कर पाते थे। टाइम-टाइम से जो अब जरूरत पड़ती है, टाइम से पैसा आता इसलिए उनको जो है यह बहुत बहुमूल्य समझ में आता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में एक हजार पांच सौ उन्नीस करोड़ रुपए की लागत वाले ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण का लोकार्पण और परियोजना के तीसरे व चौथे चरण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में लखनऊ का विकास तेज़ गति से हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश कुशल नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रदेश उसके ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।

बहनों और भाइयों, अब तो लखनऊ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक हब रूप में विकसित होते हुए और देश की रक्षा आवश्यकताओं का भी नया केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। याद करना आत्मनिर्भरता इसकी महत्वपूर्ण एक कड़ी है। दुनिया में एक आर्थिक अराजकता की स्थिति है। अनस्थितियों में हमारा देश मजबूती के साथ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाहन करते हुए आगे बढ़ रहा है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ की तहजीब के साथ उसके विकास की चर्चा भी आज दुनियाभर में हो रही है। उन्होंने कहा कि लखनऊ में ढांचागत विकास के साथ युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है।

श्री सिंह ने रक्षा क्षेत्र में लखनऊ के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश की सुरक्षा में लखनऊ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं होना चाहिए और इसके लिए उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है। लखनऊ में कई सारी डिफेंस फैसिलिटी भी स्थापित की गई हैं और ब्रह्मोस एयरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी भी अब कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जाएगी इसके कारण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को नए अवसर भी मिलेंगे और इससे मेक इन इंडिया को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी।

लोकसभा ने वर्ष- दो हजार पच्चीस-छब्बीस के लिए पूरक अनुदानों को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत सरकार ने दो लाख इक्यासी हजार करोड़ रुपये से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मांग की थी। अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मुख्य रूप से उर्वरक, खाद्य सस्बिडी और रक्षा सेवाओं पर बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए मांगी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने

समग्र व्यापक आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी योजना के लिए तीस हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है और यह पहली अप्रैल से लागू होगा।

जी-राम-जी बिल जब हम लेकर आए थे, उस समय 95 थाउजेंट करोड़ का प्रावधान किया। इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में मार्च 31 तक जो मनरेगा लागू है, उसके लिए 30 थाउजेंट करोड़, नया फस्ट अप्रैल से जी-राम-जी आने वाले हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए आज और कल लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के जरिये चार हजार पांच सौ तिरालीस पदों पर भर्ती की जाएगी। एक रिपोर्ट..
... पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी। इसके लिए लगभग 15 लाख 75 हजार 760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिखित प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी, नकलविहीन और शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी परीक्षा केन्द्रों की सीसीटीवी से मानीटरिंग के लिए त्रिस्तरीय कंट्रोल और कमांड सेंटर की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले प्रवेश पत्र और पहचान संबंधी दस्तावेज़ लेकर पहुंचें। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर जूते ना पहनकर जाने और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं या नकल संबंधी सामग्री न लेकर जाने की भी सलाह दी गई है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कल कानपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्री रिणवा ने बताया कि आगामी चुनाव में किसी भी पोलिंग स्टेशन में बारह सौ से अधिक मतदाता नहीं होंगे। साथ ही चुनाव के दौरान सभी पोलिंग स्टेशन पर टोकन लेकर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के सभी नागरिकों से दस अप्रैल को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने की अपील की है।

उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों से यह अपील भी करूंगा कि अब जो 10 अप्रैल को हमारी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी एसआईआर 2026 की उसको हर नागरिक जरूर देख ले। अगर कोई गलती है और नाम नहीं है तो फॉर्म छह भर दें। फॉर्म छह अभी भी भर सकते हैं। दावा आपत्ति अवधि तो 6 मार्च को समाप्त हो गई लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि लोग फॉर्म छह सात आठ नहीं भर सकते। वह अभी भी भर सकते हैं।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाता है। ऐसे विवाद जो अभी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उन्हें भी वाद-पूर्व सुनवाई स्तर पर लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से निपटाया जा सकता है। इसमें लोग अपने ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, भूमि विवाद, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बिजली, पानी के बिल, और बैंक वसूली जैसे मामलों को निःशुल्क और शीघ्र निपटा सकते हैं।
